

प्रेषक,

संख्या:- /XVIII(II)/2012-01(47)/2010

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक: 15 अप्रैल, 2013

विषय:- मैं खन्ना आटोमार्ट, प्रा०लि० नई दिल्ली को ग्राम मखियाली दुन्दी परगना मंगलौर जनपद हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन (हुण्डई कार शोरूम/ सर्विस स्टेशन की स्थापना) हेतु 0.369 है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-1118/भूमि व्यवस्था-2011 दिनांक-30.04.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं खन्ना आटोमार्ट प्रा०लि० नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन (हुण्डई कार शोरूम/ सर्विस स्टेशन की स्थापना) हेतु ग्राम मखियाली दुन्दी, परगना मंगलौर जनपद हरिद्वार में आपके द्वारा अनुमोदित/ संस्तुत खसरा संख्या-22म के अन्तर्गत 0.369 है० भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा- 154 (4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/ सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अगिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (हुण्डई कार शोरूम/ सर्विस स्टेशन की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/ जनजाति के

न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7— क्य की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शोरूम/सर्विस स्टेशन हेतु फैकट्री भवन निर्माण का प्लान सीड़ा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9— इकाई द्वारा क्य की जाने वाली भूमि का उपयोग कार शोरूम/सर्विस सेन्टर हेतु ही किया जायेगा।

10— इकाई को सेवा उद्यम की स्थापना हेतु सम्बन्धित जनपद में ई.एम.पार्ट-1 व ई.एम.पार्ट-2 फाईल कर उसकी अभिरचीकृति प्राप्त करनी होगी।

11. इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13— किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।

16— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत रवीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एंव इस शासनादेश के अनुपालन स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)

सचिव।

पृ०प०सं०— ३५८ / समदिनांकित / 2012

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एंव सचिव, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— प्राधिकृत हस्ताक्षरी, खन्ना आटोमार्ट, प्रा०लि०, मंगलौर रोड, रुडकी।
- 5— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
- 6— प्रभारी गीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)

अनुसचिव।